



Neutral Citation No. - 2026:AHC:173725

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 4996 सन् 2026

शशांक कुमार सिंह

..... पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

..... विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) के अधिवक्ता : बिंदु कुमारी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 86

माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि

1. पुनरीक्षणवादी की विद्वान अधिवक्ता सुश्री बिंदु कुमारी तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री पंकज कुमार को सुना गया।
2. पुनरीक्षणवादी की विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण को प्रार्थना खंड में उल्लिखित अनुतोष के साथ प्रस्तुत किया गया है। पुनरीक्षण के प्रार्थना खंड में उल्लिखित अनुतोष नीचे दिया गया है:-

“अतः, यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्वक वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण को स्वीकार करने तथा विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गौतम बुद्ध नगर द्वारा आपराधिक विविध वाद संख्या 324 सन् 2024 (श्रीमती सुकृति सिंह बनाम शशांक कुमार सिंह), धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता, थाना बिसरख, जनपद गौतम बुद्ध नगर में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 30.06.2026 को अपास्त करने की कृपा करे, जिसके द्वारा विपक्षी पक्षकार संख्या 2 द्वारा धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को अवैध रूप से स्वीकार करते हुए विपक्षी पक्षकार संख्या 2 को आवेदन की दिनांक से 8,000/- रुपये अंतरिम भरण-पोषण के रूप में प्रदान

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



किए गए हैं। और/या ऐसा अन्य एवं अग्रोतर आदेश पारित करे, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित एवं न्यायसंगत समझे, अन्यथा पुनरीक्षणवादी को अपूरणीय हानि एवं क्षति होगी।”

3. पुनरीक्षणवादी की विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गौतम बुद्ध नगर ने आदेश दिनांक 30.06.2026 के माध्यम से पुनरीक्षणवादी को उसकी पत्नी/विपक्षी पक्षकार संख्या 2 को आवेदन की दिनांक अर्थात 15.04.2024 से अंतरिम भरण-पोषण के रूप में 8,000/- रुपये प्रति माह भुगतान करने का निर्देश दिया है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि अंतरिम भरण-पोषण की धनराशि पुनरीक्षणवादी की आय के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि वह गुण-दोष के आधार पर इस पुनरीक्षण पर जोर नहीं देना चाहती हैं और इसे संबंधित परिवार न्यायालय को धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता/144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत आवेदन पर शीघ्रता से अंतिम रूप से निर्णय करने हेतु निर्देश देते हुए निस्तारित किया जा सकता है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि न्यायहित में आवेदन की दिनांक अर्थात 15.04.2024 से भरण-पोषण की धनराशि के बकाया को धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता/144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत लंबित आवेदन के अंतिम निस्तारण तक स्थगित रखा जा सकता है। उन्होंने यह वचन दिया कि यदि यह न्यायालय पुनरीक्षणवादी के उपर्युक्त अनुरोध को स्वीकार करता है, तो पुनरीक्षणवादी आदेश की दिनांक अर्थात 30.06.2026 से भरण-पोषण की धनराशि के समस्त देय/बकाया का भुगतान कर देगा और वह अपनी पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण की धनराशि का भुगतान नियमित रूप से मासिक आधार पर भी करेगा।

4. उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा न्यायहित में, आवेदन की दिनांक अर्थात 15.04.2024 से 29.06.2026 तक की अंतरिम भरण-पोषण की धनराशि के बकाया की वसूली धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता/144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत लंबित आवेदन के अंतिम निर्णय तक स्थगित रहेगी। तथापि, पुनरीक्षणवादी को आदेश की दिनांक अर्थात 30.06.2026 से भरण-पोषण की धनराशि के समस्त देय/बकाया का भुगतान करने का

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



निर्देश दिया जाता है तथा वह अपनी पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण की धनराशि का नियमित रूप से मासिक आधार पर भुगतान करता रहेगा।

5. यदि पुनरीक्षणवादी उपर्युक्त किसी भी निर्देश का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गौतम बुद्ध नगर को प्रचलित विधि के अनुसार आदेश दिनांक 30.06.2026 के अनुसार पुनरीक्षणवादी से भरण-पोषण की धनराशि के बकाया की वसूली के लिए कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी। प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गौतम बुद्ध नगर को यह निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तथा किसी अनावश्यक स्थगन की अनुमति दिए बिना, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **रजनेश बनाम नेहा एवं एक अन्य, (2021) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस 324** के प्रकरण में प्रतिपादित विधि के आलोक में, धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता/144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत लंबित आवेदन पर अधिमानतः छह माह की अवधि के भीतर अंतिम आदेश पारित करें।
6. उपर्युक्त निर्देशों के साथ, यह पुनरीक्षण **निस्तारित** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि)

18 अगस्त, 2026

मनीष हिमवान

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”